

अमेरिका व ईरान के बीच मैसेज का आदान-प्रदान कैसे हो रहा है?

संकेत हैं कि मिस्र, पाकिस्तान व खाड़ी देश, संदेशों के आदान-प्रदान में बिचौलिए का काम कर रहे हैं

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 मार्च। मध्य-पूर्व में अपने सहयोगी देशों के बीच चल रहे युद्ध के बीच संतुलन बनाकर चल रहा पाकिस्तान अब ईरान और उसके विरोधियों, अमेरिका और इज़रायल, के बीच शांति स्थापित करने के लिए खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए इस्लामाबाद अपने सेना प्रमुख के तेहरान से संबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा है।
अब तक पाकिस्तान ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा करते हुए, साथ ही तनाव कम करने की अपील करके, एक सतर्क कूटनीति अपनाई है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, अब पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और ईरान के बीच बातचीत के लिए

- पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने टर्की के विदेश मंत्री से सोमवार को बातचीत की। इसी प्रकार मिस्र के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री से वार्ता की।
- पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने ट्रंप से रविवार को बातचीत की तथा पाकिस्तान के प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशिकयन से बात की तथा दोनों ग्रुप के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया तथा बातचीत पाकिस्तान में आयोजित करने का सुझाव भी दिया।

इस्लामाबाद को एक संभावित स्थान के तौर पर पेश किया है, और बातचीत इसी हफ्ते हो सकती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, जबकि प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज़ शरीफ ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशिकयन से बातचीत की। शरीफ और पेज़ेशिकयन के बीच यह बातचीत उसी समय हुई, जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह नष्ट करने की अपनी धमकी को टालने की

घोषणा की।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए तेहरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत के बाद अपनी धमकी को रोक दिया। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन तेहरान ने यह माना कि कुछ क्षेत्रीय देश मध्यस्थता की कोशिशों में शामिल हैं।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सरकारी मीडिया आईआरएनए से कहा, “पिछले कुछ दिनों में कुछ मित्र देशों के माध्यम से

संदेश मिले, जिनमें युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की बातचीत की इच्छा जताई गई थी। इन पहलों का जवाब देश की मूल नीतियों के अनुसार दिया गया है।”प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य की स्थिति और युद्ध समाप्त करने की शर्तों को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।
ईरान की संसद के स्पीकर एम.बी. ग़ालिबाफ़ ने भी कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “फर्जी खबरों का इस्तेमाल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘धनखड़ के ईस्तीफे का असली कारण है ईडी फाइल्स’

शिव सेना सांसद संजय राउत ने अपनी किताब “अनलाइकली पैरडाइज़” में दावा किया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 मार्च। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने अपनी किताब के अपडेटेड संस्करण में दावा किया है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ईडी) और अन्य केन्द्रीय जाँच एजेंसियों के जरिए दबाव डाला था।
धनखड़ ने पिछले साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने ज्यादातर चुप्पी साधे रखी। हाल ही में उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया था। धनखड़ ने पिछले महीने चुरू के सादुलपुर कस्बे में कहा था, “मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा हूँ, जो हर किसी को देनी चाहिए।” अपनी किताब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्रेजुएट जवानों को प्रमोशन देगी सेना

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 मार्च। सैन्य-नेतृत्व को प्रभावित कर रही लगभग 8,000 अधिकारियों की कमी को देखते हुए, भारतीय सेना ने ग्रेजुएट

- सेना 8,000 अफसरों की कमी से त्रस्त है, इसलिए यह फैसला किया गया है कि ग्रेजुएट जवानों को 18 माह में प्रमोशन दिया जाएगा।

जवानों को 18 महीने के भीतर अधिकारी बनाने का फैसला किया है।
अब उन्हें अधिकारी बनने के लिए चार साल की लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी।
आर्मी कैडर कॉलेज (एसीसी) प्रवेश योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक जवानों को तीन साल पढ़ाई और एक साल ट्रेनिंग करनी पड़ती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राउत ने लिखा है कि धनखड़ को ईडी की धमकी देकर ईस्तीफे के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि धनखड़ के स्वतंत्र फैसले एनडीए सरकार को रास नहीं आ रहे थे।
- राउत की किताब मूलतः मराठी में है और मंगलवार को इसके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में कपिल सिब्बल, आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल तथा तृणमूल सांसद डैरेक ओ ब्रायन मौजूद थे।
- पुस्तक में राउत ने कहा है कि अफवाह थी कि धनखड़ व उनकी पत्नी ने अपना जयपुर स्थित घर बेचा था और इससे प्राप्त कुछ राशि विदेश भेजी थी। ईडी उन पर नजर रखे हुए थी तथा उनकी फाइल तैयार कर रही थी।
- जब धनखड़ के स्वतंत्र फैसलों पर भाजपा में असंतोष फैला तो ईडी की फाइल के जरिए उनसे ईस्तीफा लिया गया, हालांकि कहा गया कि उन्होंने बीमारी के कारण ईस्तीफा दिया, पर, हाल ही में धनखड़ ने खुद इसका खंडन किया और कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था, मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा हूँ, सभी को यह करना चाहिए।

ईरान के शीर्ष नेताओं को मारने का निर्णय किसने लिया?

ट्रंप ने पहले यह कहा कि निर्णय सामूहिक निर्णय था, उसकी सरकार का, केवल उनका अकेले का निर्णय नहीं था

- इससे पहले, उन्होंने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को मुख्य “प्रेरक” बताने का प्रयास किया और मंच पर उनके बगल में बैठे रक्षा सचिव को इंगित करके कहा, “पीट तुम सबसे पहले व्यक्ति थे, जिसने कहा था, ईरान को न्यूक्लियर हथियार प्राप्त नहीं होने देना चाहिए।”
- ट्रंप ने यह भी जताने का प्रयास किया कि उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस प्रारंभ से ही ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के खिलाफ थे।
- इस सैन्य कार्यवाही में ट्रंप की ओर से सबसे बड़ी गलती हुई कि वे मान रहे थे कि वेनेज़ुएला की भांति ईरान पर भी वे कुछ दिनों में ही जीत हासिल कर लेंगे, उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जोरदार जवाबी हमला करेगा तथा खाड़ी देशों को युद्ध में शामिल कर लेगा।
- शायद, एक नया समानान्तर कथानक प्रस्तुत करके ट्रंप विश्व को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो तो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं और थे।
- पर, अभी भी विश्व तो अमेरिका की पांच दिनों के लिए ईरान के ठिकानों पर बमबारी रोकने की घोषणा को संदेह की निगाह से देख रहा है।

के शुरुआती समर्थकों में से एक थे। उन्होंने कहा, “पीट, मुझे लगता है कि

आपने सबसे पहले कहा था कि “चलो इसे करते हैं, क्योंकि उन्हें परमाणु

हथियार नहीं रखने दे सकते,” उस समय हेगसेथ उनके बगल में बैठे थे।

रक्षा सचिव शुरू से ही प्रशासन की युद्ध-संबंधी रणनीति का सार्वजनिक चेहरा

ट्रंप ने मोदी से फोन पर बात की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 मार्च। पश्चिम एशिया संकट को समाप्त करने के लिए अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच संभावित वार्ता की खबरों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

- भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जिओ गोर ने एक्स पर यह जानकारी दी और कहा, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट पर बात की।

से फोन पर बातचीत की।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर ने एक्स पर कहा कि दोनों नेताओं ने “मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने के महत्व” पर भी बात हुई।
ट्रंप-मोदी की यह बातचीत उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि “मिडिल ईस्ट में शत्रुता को पूरी तरह खत्म करने के लिए बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत” चल रही है।
गोर की एक्स पोस्ट से कुछ घंटों पहले, ब्रिटेन के अखबार “फायनेंशियल टाइम्स” ने दावा किया कि पाकिस्तान अमेरिका-इज़रायल- (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चाचा रामचरण लाल का निधन

जयपुर, 23 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चाचाजी रामचरण लाल शर्मा का मंगलवार को निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और मानसरोवर स्थित अमर

- वे मानसरोवर स्थित अमर अस्पताल में भर्ती थे।

हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर अस्पताल में अपने चाचाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिवारजनों को ढ ाँड स बंधाया और दुख की इस घड़ी में हिम्मत बनाए रखने की बात कही। परिजनों और नजदीकी लोगों के साथ मुख्यमंत्री कुछ समय तक अस्पताल में रहे और सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
मुख्यमंत्री के इस दौर के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

‘भाजपा आई तो बंगाल में मछली पर बैन लगा देगी’

तृणमूल के इस नैरेटिव को झुठलाने के लिए घर-घर मछली बांट रहे हैं भाजपा प्रत्याशी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 मार्च। “माछे भाते बंगाली” यह सदियों पुरानी कहावत मोटे तौर पर यह बताती है कि मछली और चावल बंगाली पहचान का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में यह साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि बंगालियों की थाली पर भी लड़ा जाएगा।
ममला बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस “शाकाहार” के मुद्दे को उछालकर भाजपा को एक बाहरी ताकत के रूप में पेश कर रही है, जो सत्ता में आने पर बंगालियों की खान-पान की आदतों में दखल देगी। दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार इंटरव्यू में मछली का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां तक कि एक उम्मीदवार घर-घर प्रचार के दौरान “कतला मछली”, जो बंगाली

- मछली और भात बंगाल के खान-पान का ही नहीं, बल्कि संस्कृति का अहम हिस्सा है और तृणमूल कांग्रेस भाजपा द्वारा शाकाहार भोजन पर जोर देने को मुद्दा बना रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाजपा बाहरी पार्टी है और बंगालियों की खान-पान की आदतों को बदल देगी।

- इसी क्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बयान भी उछाला जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि राज्य में मांस-मछली की खुली बिक्री पर रोक लगाई जाएगी।

- तृणमूल का आरोप है कि जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के मीट, जैसे बीफ आदि पर रोक लगाई जाती है।

- भाजपा के लिए तृणमूल के इस नैरेटिव को झुठलाना मुश्किल हो रहा है। भाजपा पूरे जतन कर रही है, इससे पार पाने के लिए। भाजपा प्रत्याशी न केवल खुले आम मछली खाते दिख रहे हैं, बल्कि वे घर-घर मछली बांट भी रहे हैं।

घरों का एक प्रमुख भोजन है, साथ लेकर जा रहा है।
चुनावी मौसम में भाजपा द्वारा मछली के प्रति सार्वजनिक आकर्षण के

इस प्रदर्शन का उद्देश्य साफ तौर पर तृणमूल के नैरेटिव का जवाब देना है। भाजपा जानती है कि बंगाली मतदाता अपनी संस्कृति और खान-पान के प्रति

बेहद संवेदनशील है और “बाहरी” होने की छवि उसकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली, 24 मार्च। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार को अचानक बिगड़ गई है। उन्होंने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी को फेफड़े से संबंधित समस्या के कारण अस्पताल में दाखिल किया गया है।

- मंगलवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल में मौजूद हैं।

उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी अस्पताल में मौजूद हैं। परिवार के सदस्य उनकी सेहत पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं।
अस्पताल प्रशासन ने उनकी वर्तमान स्थिति को स्थिर बताया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रहे हैं, नियमित रूप से मीडिया को जानकारी दे रहे हैं और अभियान का बचाव कर रहे हैं।
हालांकि ट्रंप ने यह भी रेखांकित किया कि यह निर्णय एकतरफा नहीं था। उन्होंने कहा “मैंने पीट को फोन किया। मैंने जनरल केन को फोन किया। मैंने हमारे कई दिग्गजों से बात की”, ट्रंप ने इस निर्णय को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ विचार-विमर्श का परिणाम बताया। इस फैसले को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास मध्य पूर्व में एक समस्या है और हम वहां जाकर एक बड़ी समस्या को खत्म कर दें” युद्ध को लेकर ट्रंप के अपने स्पष्टीकरण काफी अस्पष्ट व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

संसार के विरुद्ध खड़े रहने के लिए शक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ईसा दुनिया के खिलाफ खड़े रहे, बुद्ध भी अपने जमाने के खिलाफ गए, प्रहलाद ने भी वैसा ही किया। ये सब नम्रता के धनि थे। अकेले खड़े रहने की शक्ति नम्रता के बिना असंभव है। –महात्मा गाँधी

सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत का बड़ा कदम

भारत बहुत लंबे समय से सेमीकंडक्टर का उत्पादन बनने के प्रयासों में लंबे समय से लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन का क्षेत्र अत्यंत मुश्किल है जिसमें उतरने के लिये किये गए प्रयासों में कई धक्के भी लगे हैं। चालीस साल पहले 1980 के दशक में मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगने से भारत की शुरुआती महत्वाकांक्षी शुरुआत को ऐसा झटका लगा जिससे उबरने में इतना समय लग गया। बाद में 2000 के दशक में, भारत फिर मौका चूक गया जब इंटेल् के प्रस्तावित मैनुफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को हासिल करने में वह नाकाम रहा। इस तरह दिसंबर 2021 में जब केंद्र सरकार के ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ शुरू करने किया तब भी आशंका बनी रही क्योंकि वेदांता-फॉसस्कोर्न जॉइंट संचर टूट गया था। बात तब बनती फिर नजर आई जब माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के साणंद में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी बनाने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान किया। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इसलिए अहम था कि यह भारत का पहला बड़े पैमाने का कर्मशियल सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट था, बल्कि इसलिए भी कि यह एक जानी-मानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी से आया था। मांझ्युल बनाने वालों और इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों के लिए, यह एक बड़ी कामयाबी थी। नीतियों और इनके क्रियान्वयन पर निगाह रखने वालों के अनुसार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, ऐलान अधिक मायने नहीं रखते, अमल मायने रखते हैं। अब, जब माइक्रोन का साणंद प्लांट कर्मशियल ऑपरेशन में जा रहा है, तो स्वाभाविक ही ऐलान असलियत में बदल रहा है। फिर भी यह संदेह भी बना हुआ है कि क्या यह प्रोजेक्ट ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भारत के लिये जगह बना पायेगा और क्या यह आगे के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकेगा?

माइक्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की लीडिंग मेमोरी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है। इसकी साणंद फैसिलिटी सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग के बैकएंड स्टेज पर काम करती है, जहां फैब्रिकेशन प्लांट में बनाए गए वेफर्स को कस्टमर्स को भेजने से पहले असेंबल, टेस्ट और पैक किया जाता है। भारत की पहली हाई-वॉल्यूम मेमोरी असेंबली और टेस्ट साइट है। जहां पांच लाख स्वचायर-फुट का क्लीनरूम दुनिया भर में सबसे बड़ा सिंगल रेज्ड-फ्लोर सेमीकंडक्टर असेंबली क्लीनरूम है। इसे क्रिटिकल एरिया में क्लास 1,000 स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, जो मेमोरी मैनुफैक्चरिंग में ज़रूरी प्रिसिजन और कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। साणंद प्लांट के लिए, वेफर्स माइक्रोन के ग्लोबल फैब्रिकेशन नेटवर्क से लिए जाएंगे। बाद में भारत में ही वेफर थ्रिनिंग, असेंबली, टेस्टिंग और मांझ्युल बनाये जाएंगे। इसे ‘वेफ़र-इन से फिनिश-प्रोडक्ट-आउट प्रोसेस’ कहते हैं। यहां पर्सनल कम्प्यूटर, स्मार्टफ़ोन, डेटा सेंसर और स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए डीआरएएम और एनएएनडी उपकरण बनाये जाएंगे। ये उत्पाद न केवल नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ग्लोबल कस्टमर्स को सेवा देंगे, साथ ही घरेलू सप्लाई को भी मजबूत करेंगे। बताया गया है कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद, साणंद फैसिलिटी से माइक्रोन के ग्लोबल पैकेजिंग और टेस्ट आउटपुट का लगभग दस प्रतिशत काम हो जाने की उम्मीद है। यह प्लांट दिखाता है कि एडवांस्ड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग ऑपरेशन ग्लोबल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड का पालन करते हुए भारत अपनी क्षमता बना सकता है। इसीलिए भारत के सेमीकंडक्टर पुश पर निगाह रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि माइक्रोन का ऑपरेशनल प्लांट देश के लिये एक ज़रूरी क्रेडिबिलिटी का संकेत देता है।

वास्तव में जून 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की घोषणा के बाद से ही इसका असर दिखने लगा था। यह असर इस बात से स्पष्ट है कि उसके बाद सात और ओसेट परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कई पाइपलाइन में हैं। विशेषज्ञ हालांकि, वह चेतावनी भी देते हैं कि इस क्षेत्र में भविष्य के इन्वेस्टमेंट इस बात पर निर्भर करेंगे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पैकेजिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे और कितनी प्राथमिकता देता है। जहां तक फैब्रिक की बात है, किसी देश में पैकेजिंग फैसिलिटी होने का मतलब यह नहीं है कि फैब्स अपने आप अपना काम शुरू कर देंगे। फिर भी, यह बात कि माइक्रोन का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन तक आगे बढ़ गया है, इससे लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को दूर करने में मदद मिली है। इस प्रोजेक्ट ने भारत इस सोच को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है कि देश एक हाई-एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन देने के लिये तैयार है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि हालांकि यह अभी एक स्ट्रेटेजिक असर है, और उसे कैपेसिटी वाला असर

माइक्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की लीडिंग मेमोरी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है। इसकी साणंद फैसिलिटी सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग के बैकएंड स्टेज पर काम करती है, जहां फैब्रिकेशन प्लांट में बनाए गए वेफर्स को कस्टमर्स को भेजने से पहले असेंबल, टेस्ट और पैक किया जाता है। भारत की यह पहली हाई-वॉल्यूम मेमोरी असेंबली और टेस्ट साइट है। जहां पांच लाख स्वचायर-फुट का क्लीनरूम दुनिया भर में सबसे बड़ा सिंगल रेज्ड-फ्लोर सेमीकंडक्टर असेंबली क्लीनरूम है।

की जरूरत होती है। भारत के नीति निर्माताओं से अपेक्षा होगी कि माइक्रोन की साणंद परियोजना एक स्टैंड अलोन आउटपुट बनकर न रह जाय, बल्कि एक एंकर इन्वेस्टमेंट बने और यह लगातार पॉलिसी फिटन्यूटी और इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर निर्भर करेगा। क्योंकि चिप मैनुफैक्चरिंग बहुत आसान काम नहीं है इसलिए माइक्रोन का प्लांट चालू होने के बाद भी, देश में सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर निर्भर करेगी। उसके लिये चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली, पानी की उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। कंपनियों को मोज़जूदगी भी उतनी ही जरूरी होगी, जिसमें सबस्ट्रेट मैनुफैक्चर्स, मटीरियल सप्लायर्स और इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ के साथ को-लोकेट कर सकें। सबसे अहम है एक स्क्रिडल वर्कफोर्स की पाइपलाइन और एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज़, जिनमें हेटेरोजिनस इंटीग्रेशन शामिल है। इसके लिए एक रोडमैप भी बहुत जरूरी है।

जानकारों का कहना है कि माइक्रोन का साणंद प्रोजेक्ट भारत के सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी के कुछ हिस्सों को जकर वैंलिटेट करता है, लेकिन केवल इससे पूरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि बैकएंड मैनुफैक्चरिंग, जैसे असेंबली और टेस्टिंग, में वेफर फैब्रिकेशन की तुलना में कम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्प्लेक्सिटी होती है। माइक्रोन का प्रोजेक्ट दिखाता है कि एक कंट्रीड डंडस्ट्रियल ज़ोन के अंदर, भारत सेमीकंडक्टर टाइमलाइन के हिसाब से भरोसेमंद बिजली, पानी, ज़मीन तक पहुंच और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन दे सकता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की विश्वसनीयता को लेकर पहले के संदेह दूर हो जाते हैं। फिर भी ढांचगत रिस्क बने हुए हैं। कई राज्यों में ऐसी स्थितियाँ को दोहराना, बढ़ते इंडस्ट्रियल लोड के तहत बिजली की ग्रिड स्ट्रेबिलिटी मजबूत करना, एक सप्लायर इकोसिस्टम बनाना और भविष्य के फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए तैयारी करना, अगली चुनौतियां होगी। भारत को एशिया के चिप हब के साथ अपने अंतर को कम करना होगा। भले ही भारत बैकएंड सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग में अपने पहले कदम उठा रहा है, फिर भी यह एशिया के स्थापित सेमीकंडक्टर क्लस्टर से बहुत पीछे है। मलेशिया, चीन और जापान जैसे देशों ने पैकेजिंग फर्म्स, इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स, केमिकल सप्लायर्स और स्पेशलाइज्ड लेबर पूल्स में फैली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने में दशकों लगाए हैं। उनके फ़ायदों को हमारे वहां जल्दी से दोहराना नहीं जा सकता। मलेशिया में, हालांकि सरकारी कंट्रोल और चीन के लिए बैकडोर होने की चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक अनुभवी प्लेयर होने का उसे फायदा है। जापान टेक्नोलॉजी में लीडर है, खासकर जब सप्लाई चेन की बात आती है। मगर वह फैब टेक के साथ नहीं चल पाया है और कुछ हद तक उसकी बढ़ती उम्र और घटती आबादी की वजह से उनके पास टैलेंट की भी कमी है। चीन के पास टेक्नोलॉजी, टैलेंट और पैसा सब कुछ है। हालांकि, दुनिया भर में उस पर भरोसे की कमी उसके लिये एक नेगेटिव बात है। ऐसे में इन देशों की तुलना में, भारत के फ़ायदे सामने आ रहे हैं।

यहां टैलेंट एक ऐसा एरिया है जहां प्रोग्रेस पहले से ही दिख रही है। माइक्रोन की साणंद फैसिलिटी में लगभग 1,300 कर्मियों में से लगभग 700 गुजरात और आस-पास के राज्यों के नए कॉलेज ग्रेजुएट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रियल और मटीरियल इंजीनियरिंग के इन ग्रेजुएट ने भारत में ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए मलेशिया और सिंगापुर की एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी में 3-6 महीने की इंटेसिव ट्रेनिंग पूरी की है। हालांकि, टेक्नोलॉजी कंपैबिलिटी और सप्लाई चेन डेप्थ बनाने में ज्यादा समय लगेगा। भारत के लिए समय के साथ सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मटीरियल सप्लायर, पैकेजिंग सबस्ट्रेट और स्पेशल इक्विपमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एक लोकल इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी होगा। जियोपॉलिटिकल विंडो की भी बात आती है। भारत को बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से भी फ़ायदा हो सकता है। चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी रीअलाइनमेंट के बीच, मल्टीनेशनल कंपनियों सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी पर तेज़ी से विचार कर रही हैं। इससे भारत को एक पोर्टेशियल ओपनिंग मिलसकती है। हालांकि आज भी भारत के फ़ायदे इकोसिस्टम के बजाय पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स से ज्यादातर प्रभावित हैं। माइक्रोन के साणंद प्लांट ने भारत को एक ज़रूरी क्रेडिबिलिटी थ्रेशहोल्ड पार करने में मदद की है। उस क्रेडिबिलिटी को सप्लायर्स, टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक गहरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बदलना अगली असली मुश्किल चुनौती होगी।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



मदन राठौड़

राजस्थान दिवस के अवसर पर जारी आंकड़े प्रदेश की विकास यात्रा का ठोस दस्तावेज़ है। यह आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अल्प समय में ही पकड़ी प्रगति की नई रफ्तार से विकसित राजस्थान का संकल्प साकार हो रहा है। इनकी तुलना पिछली सरकार के कार्यकाल से की जाती है, तो अंतर केवल संख्याओं के साथ ही दृष्टिकोण, कार्यसंस्कृति और परिणामों में भी स्पष्ट नज़र आता है।

वर्तमान सरकार ने सत्ता संपालते ही विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ किया। यही कारण है कि अनेक योजनाओं में राजस्थान देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी होना इस बात का प्रमाण है कि किसानों

को सुरक्षा कवच प्रदान करने में राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। पोषण-कुपोषण योजना के कंपोनेंट-ए एवं सी के सफल क्रियान्वयन ने सामाजिक क्षेत्र में भी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। कृषि विभाग की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, किसानों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण में तेजी और पारदर्शिता जैसे कदम पूर्ववर्ती सरकार की धीमी कार्यप्रणाली से स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं।

पर ड्रांप – मोर क्राॅप योजना के तहत 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और किसानों की आय बढ़ाने का भी मजबूत माध्यम बना है। पशुपालन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का प्रमाण है कि राज्य को डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की योजनाओं में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। धरती आबा जन्मगोदारी अभियान में ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफलता पाई है।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले 5 वर्षों (2018-2023) की तुलना में वर्तमान सरकार के लगभग 25 माह (2024-2026) के

कार्यकाल में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ी है पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण के तहत 2.35 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, वर्तमान सरकार ने मात्र लगभग 25 महीनों में 3.41 लाख को प्रशिक्षित किया गया। कृषि क्षेत्र में पहले 29,430 फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) बनाए गए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 35,368 हो चुकी है।

ऊर्जा और सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले 13,160 सोलर पंप स्थापित किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 16,864 हो गई है। पर ड्राॅप-मोर क्राॅप जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन स्थापित कर जल प्रबंधन को नई दिशा दी है।

ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले जहां केवल 1,478 गांव इससे जुड़े थे, वहीं अब यह आंकड़ा 41,037 गांवों तक पहुंच गया है। पहले 1,104 गांव सड़कों से जुड़े थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1,717 हो गई है। मनरेगा के तहत सृजित मानव दिवसों में तो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पहले जहां 22,597 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 98,894 लाख मानव दिवस तक पहुंच गया है।

ढाणियों के विद्युतीकरण में पहले 3,952 कार्य हुए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 8,261 हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत जहां पहले 2,92,507 घरों को नल कनेक्शन

मिले थे, वहीं अब यह बढ़कर 3,14,530 हो चुका है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जहां 489 स्वयं सहायता समूह सक्रिय थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2,911 हो गई है।

प्रशासनिक सुधारों से जहां पहले केवल 986 पट्टों का वितरण हुआ था, वहीं वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 88,724 तक पहुंचा दिया है। कृषि कनेक्शन के क्षेत्र में पहले 21,136 कनेक्शन दिए गए थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 41,820 हो गई है। उच्च शिक्षा में जहां पहले केवल 5 महाविद्यालय स्थापित हुए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21 हो गई है।

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपखंड कार्यालय भवन निर्माण में पहले मात्र 57 भवन बने थे, अब यह संख्या बढ़कर 185 हो गई है। सड़क निर्माण में पहले 10.36 हजार किमी, अब 11.31 हजार किमी निर्माण हुआ है। व राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले 1,517 किमी, अब 2,294 किमी निर्माण हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले जहां 10 मैडिकल कॉलेज थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 18 हो गई है। स्कूल अप्रोडेशन में पहले 113 करोड़ रुपये, अब 403 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पुलिस थानों के अप्रोडेशन में पहले जहां केवल 57 कार्य हुए थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 2,064 हो गई है।

आंकड़ों का यह अन्तर शासन की कार्यशैली का परिणाम है। पिछली सरकार पर अवसर धीमी निर्णय

प्रक्रिया, भ्रष्टाचार के आरोप और योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई के आरोप लगाते रहे, वहीं वर्तमान सरकार ने गुड गवर्नेंस और डिलीवरी को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर उनकी संवेदनशीलता और समझ अधिक गहरी है। यही कारण है कि योजनाएं कागजों से बाहर निकलकर खेतों और गांवों तक पहुंच रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन भी इस प्रगति का एक बड़ा कारण है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं में राजस्थान की अग्रणी भूमिका यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल से विकास को नई गति मिलती है। राजस्थान में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि विकास अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। अल्प समय में ही अनेक क्षेत्रों में कई गुना वृद्धि यह संकेत देती है कि विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने जो कार्य संस्कृति स्थापित की है, वह तेज होने के साथ ही परिणामोन्मुखी भी है। यही कारण है कि राजस्थान आज अपने अतीत की विरासत पर गर्व कर रहा है और अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

–मदन राठौड़, राज्यसभा सदस्य।

ईरान युद्ध : ऊर्जा संकट के साए में तीसरे महायुद्ध की दहलीज पर विश्व व्यवस्था



डॉ. योगेश शर्मा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन का वह कालजयी कथन आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की धुरी बना हुआ है कि राष्ट्री के न तो कोई शाश्वत मित्र होते हैं और न ही शाश्वत शत्रु, केवल उनके हित ही शाश्वत होते हैं और उनका अनुसरण करना ही परम कर्तव्य है। वैश्विक राजनीति के इस यथार्थवादी धरातल पर राष्ट्रीय हित, शक्ति-संतुलन और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। यही कारण है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, टकराव और सहयोग के नए-एनए रूप समय-समय पर उभरते रहते हैं। मध्य पूर्व में 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले के बाद उत्पन्न स्थिति इसी परिवर्तनशील और हित-आधारित राजनीति का एक अत्यंत जटिल और खतरनाक उदाहरण है, जो न केवल मिडिल ईस्ट प्रकल्प में अस्थिरता को बढ़ाएगा बल्कि संपूर्ण वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिरता को एक अभूतपूर्व संकट की ओर धकेलती प्रतीत हो रही है।

पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व का इतिहास गवाह है कि यहाँ भूगोल ही भाग्य का निर्धारक रहा है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित यह क्षेत्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के बीच एक

ऐसी भू-राजनीतिक स्थिति रखता है, जहाँ से वैश्विक व्यापार की धमनियाँ गुजरती हैं। हॉर्मुज जलडमरूमध्य, बाब-एल-मंदेब और स्वेज नहर जैसे समुद्री मार्ग पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवर रेखा हैं।

शीत युद्ध के दौर से ही यह क्षेत्र अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति-प्रतिस्पर्धा की रणभूमि बना रहा है। इजराइल और अरब देशों के बीच भू-क्षेत्र और पहचान को लेकर चलने वाले संघर्षों ने यहाँ की मिट्टी को कभी शांत नहीं होने दिया। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति में शाह पهلवी के पश्चिम समर्थक शासन के पतन के बाद अयातुल्लाह खुमेनी के नेतृत्व में ईरान एक कट्टर अमेरिका-विरोधी राज्य के रूप में उभरा। तेहरान में 52 अमेरिकी राजनयिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखने की घटना ने संबंधों में जो कड़वाहट पैदा की, उसकी गूँब आज भी सुनाई देती है।

2026 का यह वर्तमान युद्ध आधुनिक संघर्ष का एक नया और विशाखी स्वरूप लेकर आया है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो शुरुआती चरण में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की खबरों ने पश्चिम को यह विश्वास दिलाया कि यह युद्ध शीघ्र ही उनके पक्ष में गिनौक रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत निकली। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान को इस प्रकार के हमले का पूर्वानुमान था और उसने पहले से ही एक बहुस्तरीय तथा विकेंद्रित सैन्य रणनीति तैयार कर रखी थी। शीर्ष नेतृत्व पर हुए प्रहार के बावजूद ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया अधिक संगठित और व्यापक होकर सामने आई। विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित करने की ईरान की धमकी ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। विश्व की ऊर्जा

आपूर्ति के इस प्रमुख मार्ग पर रोक की आशंका मात्र से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई हैं। ईरान की रणनीति ने क्षेत्र में व्यापक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए खाड़ी देशों सहित मध्य पूर्व के अन्य संवेदनशील बुनियादी ढाँचों की भी निशाना बनाना शुरू किया है। इसका स्पष्ट उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों पर युद्धविराम के लिए वैश्विक स्तर पर मनोवैज्ञानिक दबाव और एक गहरा आर्थिक संकट उत्पन्न करना है।

इस संघर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम यह है कि रातो रात, जो सामान्यतः अमेरिका के सबसे विश्वसनीय सहयोगी माने जाते हैं, इस बार ईरान संकट पर एकमत नहीं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस प्रकार यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मित्रकण यूक्रेन को व्यापक सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वैसे एकजुटता यहाँ नदारद है। यूरोपीय देशों का एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग इस बात पर जोर दे रहा है कि इस संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए था। इसी प्रकार जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी इस संघर्ष में खुलकर समर्थन देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। ये देश भली-भाँति जानते हैं कि यह संघर्ष उस क्षेत्र में हो रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता का केंद्र है। कोई भी व्यापक सैन्य टकराव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर ऐसी रणनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है जिससे उबरना दशकों तक संभव नहीं होगा।

ईरान और अमेरिका के बीच इस लंबे टकराव का एक बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी रहा है। 2015 में हुआ परमाणु समझौता (JCPOA), जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने

और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से बाहर होने के निर्णय ने क्षेत्र में तनाव की एक नई लहर पैदा कर दी। पिछले कुछ वर्षों में अब्राहम समझौते (JCPOA), के माध्यम से इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण और 22 (भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई) जैसे समूहों के गठन से एक नए आर्थिक मॉडल की उम्मीद जगी थी। लेकिन वर्तमान युद्ध ने इन सभी नई भू-राजनीतिक संरचनाओं की सीमाओं और उनकी नाजुकता को उजागर कर दिया है।

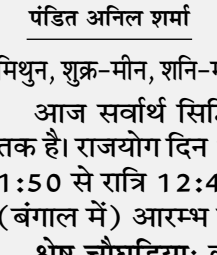
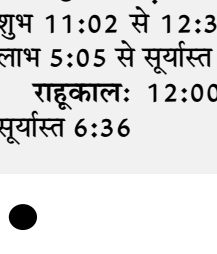
इस संघर्ष के बीच प्रत्येक राष्ट्र अत्यंत सावधानी और संतुलन के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है, जो उनकी रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है। चीन, जो ईरान के तेल का एक प्रमुख आयातक है और जिसके साथ उसके दीर्घकालिक ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचागत समझौते हैं, ने प्रत्यक्ष टकराव से बचने की नीति अपनाई है। रूस ने भी अपने भू-राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए अब तक बहुत ही सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी है। भारत के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति यहाँ कसौटी पर है। एक ओर भारत के अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक और तकनीकी संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान और मध्य पूर्व के साथ उसके ऐतिहासिक, प्रमुख आयातक और ऊर्जा आधारित संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच के लिए एक रणनीतिक द्वार के रूप में विकसित किया था, इस युद्ध और कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वर्तमान में शिथिलता का शिकार हो गया है।

निष्कर्षतः, यह पूरा घटनाक्रम

इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईरान का यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह गया है, बल्कि इसने वैश्विक राजनीति को एक अत्यंत जटिल और अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगातार बढ़ रहे ऊर्जा संकट से आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, शेयर बाजार और सोना-चांदी की कीमतों में निरंतर अस्थिरता ने नए भूआर्थिक संकट को समूहों के गठन से एक नए आर्थिक मॉडल की उम्मीद जगी थी। लेकिन वर्तमान युद्ध ने इन सभी नई भू-राजनीतिक संरचनाओं की सीमाओं और उनकी नाजुकता को उजागर कर दिया है।

इस संघर्ष के बीच प्रत्येक राष्ट्र अत्यंत सावधानी और संतुलन के साथ अपने कदम बढ़ा रहा है, जो उनकी रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है। चीन, जो ईरान के तेल का एक प्रमुख आयातक है और जिसके साथ उसके दीर्घकालिक ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचागत समझौते हैं, ने प्रत्यक्ष टकराव से बचने की नीति अपनाई है। रूस ने भी अपने भू-राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए अब तक बहुत ही सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया दी है। भारत के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति यहाँ कसौटी पर है। एक ओर भारत के अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक और तकनीकी संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान और मध्य पूर्व के साथ उसके ऐतिहासिक, प्रमुख आयातक और ऊर्जा आधारित संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह, जिसे भारत ने मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच के लिए एक रणनीतिक द्वार के रूप में विकसित किया था, इस युद्ध और कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वर्तमान में शिथिलता का शिकार हो गया है।

–डॉ. योगेश शर्मा,
(लेखक विश्वप्रसिद्ध अध्येता और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं)

राशिफल मंगलवार 25 मार्च, 2026	
	चैत्र मास, शुक्ल पंचमि, सप्तमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2083, मृगशिरा नक्षत्र सायं 5:33 तक, सौभाग्य योग रात्रि 03:09 तक, वणिज करण दिन 1:50 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।
	गृहस्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
	आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सायं 5:33 तक है। राज्योगि दिन 1:50 तक रहेगा। आज भद्रा दिन 1:50 से रात्रि 12:49 तक रहेगी। आज से दुर्गा पूजा (बंगाल में) आरम्भ होगा।
	श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से 9:31 तक, शुभ 11:02 से 12:33 तक, चर 3:35 से 5:05 तक, लाभ 5:05 से सूर्यास्त तक।
	राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:30, सूर्यास्त 6:36

	मेघ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लाभप्रवीं ठीक नहीं रहेगी।	
	वृष
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनें लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।	
	मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता का कारण होगा। महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन होगा। नैकरोपेक्षा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रयुक्त रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	
	कर्क
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनानुषंगिक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भाग्यदुःख होगी। समय अंगत्त कार्यों में खराब रहेगी। इनमें में असंतोष बढना होगा।	

राजस्थान इंटेलिजेंस ने सुमित कुमार से पूछताछ के बाद जांच का दायरा बढ़ाया

सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस आरोपी सुमित कुमार के ‘बीकानेर कनेक्शन’ पर है

बीकानेर, (निसं)। असम के छबुआ एयरफोर्स स्टेशन से गिरफ्तार सिविलकर्मी सुमित कुमार से पूछताछ के बाद अब राजस्थान इंटेलिजेंस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस सुमित के ‘बीकानेर कनेक्शन’ पर है। उसने नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर से जुड़ी जानकारीयां अपने पाक हैडलर्स को दी है। आरोपी सुमित कुमार, जो असम के डिब्रूगढ़ में कार्यरत था, उसने सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील नाल की रेकी कब की और यहां वह किसके संपर्क में रहा, इसे लेकर जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ सेंटर में संयुक्त पूछताछ जारी है। बीकानेर में नाल एयरफोर्स स्थित

- आरोपी सुमित कुमार ने सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील नाल की रेकी कब की और यहां वह किसके संपर्क में रहा, इसे लेकर जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ सेंटर में पूछताछ जारी**
- पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी वर्ष, 2023 से पाक खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और रूप्यों के लालच में जासूसी कर रहा था, छबुआ के साथ ही उसने नाल एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयां पाक हैडलर्स को दी है**

हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान से लगती पश्चिमी राजस्थान की सीमा और बाँडर जिलेबीकानेर में होने के कारण यह हवाई अड्डा अति संवेदनशील माना जाता है।

एडीजी इंटेलीजेंस प्रफुल्ल कुमार के मुताबिक जनवरी, 26 में जैसलमेर निवासी झवराराम की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पूछताछ और अनुसंधान के दौरान के बाद परतें खुली और संदिग्ध सुमित कुमार का नाम सामने आया,

जो लगातार पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था। यूपी में लाहुरापर प्रयागराज निवासी सुमित कुमार (36) असम के डिब्रूगढ़ में छबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर एमटीएस के पद पर कार्यरत था। उसने वहां और बीकानेर नाल एयरफोर्स की गुप्त सूचनाएं जुटाकर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान भेजी है। सुमित बीकानेर कब और कैसे आया, यहां कितने दिन और किसके पास रहा, राजस्थान इंटेलीजेंस पूछताछ कर रही है।

गौरतलब है कि राजस्थान इंटेलीजेंस की टीम ने एयरफोर्स इंटेलीजेंस, नई दिल्ली के साथ मिलकर सुमित को छबुआ से डिटेन किया और जयपुर स्थित केंद्रीय पूछताछ केंद्र लाया गया। वहां संयुक्त

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी वर्ष, 2023 से पाक खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और रूप्यों के लालच में जासूसी कर रहा था। छबुआ के साथ ही उसने नाल एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयां पाक हैडलर्स को दी है। इनमें लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम आदि की गोपनीय जानकारी शामिल है। आरोपी अपने नाम से जारी मोबाइल नंबरों के जरिए पाक हैडलर्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में भी मदद करता था। आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 एवं बीएनएस, 23 की धाराओं में स्पेशल पुलिस स्टेशन, राजस्थान जयपुर में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

अवैध हथियार बनाने की फैक्टरी का पर्दाफाश

गांव कांकनियावास में पांच साल से अवैध हथियार बनाये जा रहे थे

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने गांव कांकनियावास में दबिश देकर पिछले पांच साल से अवैध हथियार बना रहे आदतन बदमाश को गिरफ्तार कर पांच हथियार बरामद किये हैं। प्रारम्भिक जांच में आरोपी बीआरसी गैंग से जुड़ा हुआ होने के संकेत मिले हैं और यूट्यूबचूब को देखकर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया।

पंचर बनाने की दुकान में अवैध हथियार बनाकर पुलिस की गिरफ्त में आये आरोपी गांव कांकनियावास निवासी मोहम्मद रोशन से पूछताछ की जा रही है कि इसने किन-किन लोगों को हथियार सप्लाई किये हैं। मौके से एक नवीन टोपेदार बंदूक, एक पुरानी बंदूक, 3 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 5 कट्टों की नाल सहित हथियार बनाने में इस्तेमाल ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, बोरिंग मशीन, बारूद व अन्य टूलकिट जब्त किये हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस

- पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पांच अवैध हथियार बरामद किये**
- हथियार बनाने में इस्तेमाल ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, बोरिंग मशीन, बारूद व अन्य टूलकिट भी जब्त**

अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार के सुपरविजन में सहायक पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सीओ ग्रामीण आयुष वशिष्ठ, बांदरसिंदरी थाना प्रभारी दयाराम चौधरी टीम में शामिल रहे। हैड कांस्टेबल सांवरलाल व कांस्टेबल कालुराम का विशेष योगदान रहा।

गंगापुर सिटी में खेत में मानव शव के अवशेष मिले

गंगापुर सिटी, (निसं)। समीपवर्ती गांवड़ी गांव में एक खेत में बने पानी के टांके के पास अज्ञात मानव शव के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया।

जानकारी के मुताबिक खेत में काम कर रहे लोगों ने टांके के तनदीक संदिग्ध अवस्था में मानव अवशेष देखे, उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर जांच शुरू की और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव के अवशेषों को अपने कब्जे में लेकर गंगापुर सिटी के जिला

- सदर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए मानव शव के अवशेष**
- पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया**

अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, ये

अवशेष लगभग 1 से 2 माह पुराने प्रतीत हो रहे हैं, जिससे मृतक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक की पहचान सुरिश्चित करने के लिए शव के अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पुलिस आसपास के क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की भी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस फिलहाल सभी संभावित पहलुओं पर गौर करते हुए जांच में जुटी है। उसका प्रयास है कि मृतक की पहचान हो सके और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा किया जा सके।

अजमेर : एम.डी.एस.यू. में परीक्षा के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर बवाल

एनएसयूआई नेता हिरासत में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया

अजमेर, (कासं)। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू) में परीक्षा के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र राजनीति में उबाल आ गया। एनएसयूआई के जिला देहात अध्यक्ष अंकित धारू को ज्ञापन सौंपने से पहले ही पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद विवाद गहरा गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं के दौरान समय प्रबंधन, परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर कर क्खामियां सामने आई हैं। इन मुद्दों को लेकर संगठन डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहता था, लेकिन क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अंकित धारू को मौके से हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। सूचना मिलते ही कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता क्लॉक टावर थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।



महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने हंगामा किया।।

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्र हितों की आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।

अंकित धारू को हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्लॉक टावर थाने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने

- एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं के दौरान समय प्रबंधन, परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर कई खामियां सामने आई हैं**

पुलिस कार्रवाई और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षाओं के दौरान कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें परीक्षा प्रबंधन की कमी, समय व्यवस्था में गड़बड़ी और अन्य प्रशासनिक खामियां शामिल हैं। छात्र संगठन इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रहा था और इसी सिलसिले में ज्ञापन देने की योजना बनाई गई थी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा

करते हुए कहा कि भाजपा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएसयूआई नेता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जब कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंचे तो उनके साथ भी उचित व्यवहार नहीं किया गया। राठौड़ ने दोषी पुलिसकर्मीयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से समझाझक कर मामला शांत करवाया। पुलिस थाना परिसर में धरने पर कांग्रेस कमेटी के शैलेश अय्यथ राजकुमार जयपाल, शैलेन्द्र अग्रवाल, निमल बेरवाल, पार्षद सुनिल धानका, हेमराज खारोलिया व सुनिल लारा सहित कई कांग्रेस कार्यर्ता व पदाधिकारी बैठे।

नोखा में हमलावरों ने ट्रक ड्राइवर की कस्सी से वार कर हत्या की

हमलावरों ने घर में घुसकर ट्रक ड्राइवर का मर्डर किया, सिर पर कई वार किए

नोखा, (निसं)। थाना क्षेत्र के रासीसर गांव में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर पर कस्सी से कई वार किए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस फिलहाल हत्यारों की तलाश में जुटी है।

नोखा थानाधिकारी अरविंद्र भारद्वाज ने बताया कि रासीसर निवासी अनिल बिश्नोई पेशे से ट्रक ड्राइवर था। वह ट्रक लेकर रासीसर आया और गांव के एक होटल के पास खड़ा कर अपने घर नहाने चला गया। वह दिनभर घर पर ही था। शाम के समय पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदारों ने उसे चाय पीने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर घर के अंदर देखने पहुंचे तो गेट के पास अनिल बिश्नोई का शव लहलुहान हालत में पड़ा मिला। परिजनों और पुलिस को तुरंत

- मौके पर पुलिस, एफएसएल और एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच की**
- पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है**

सूचना दी गई। सूचना मिलने पर नोखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस को मौके से खून से सनी एक कस्सी बरामद हुई है। शुरुआती जांच में आशंका है कि अज्ञात हमलावरों ने इसी कस्सी से सिर पर कई वार कर अनिल की हत्या की। शव के आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और एमओबी (मोबाइल आउटपुट ब्यूरो) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र में

जांच-पड़ताल की। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी ग्रामीण बनवारीलाल मीणा और नोखा सीओ जरनैल सिंह भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस टीम को मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है।

युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी

जोधपुर, (कासं)। सांगरिया ब्रिज रेलवे ट्रैक का एक युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। पिता का आरोप है कि पुत्रवधु और अन्य मिलकर उसे तंग और परेशान करते थे, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। कुड़ी भगतसनी थाने में इस बाबत केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने शव को कार्रवाई के बाद परिजन के सुपुर्द किया। अग्रिम कार्रवाई जारी है।

थानाधिकारी तेजवरण ने बताया कि राजपूतों का बास, झालामंड निवासी 28 वर्षीय प्रकाश राव पुत्र प्रेमराम राव ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। उसकी पहचान के साथ शव का बाद में पोस्टमार्टम कराया गया। उसके पिता प्रेमराम का आरोप है कि उसके पुत्र प्रकाश को उसकी पत्नी और अन्य लोग तंग और परेशान करते थे, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।

बदमाशों ने युवक से मारपीट की

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के एक सुलभ शौचालय में लूट की नितय से एक युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में पारस चौराहा के पास मुख्य सड़क की है। पीड़ित युवक को फरमट टोल्येट करने गया था। अंदर घुसते ही एक बदमाश ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। तुरंत उसके दो अन्य साथी भी अंदर आ गए और तीनों ने मिलकर युवक को बुरी तरह पीटा। उन्होंने मोबाइल छीने और पैसे लूटने की कोशिश की।

राजस्थान सरकार			
कोटेशन शिक्षा विभाग			
Website: https://hrte.rajesthan.gov.in/college/gcsanchore Email: info@rajesthanchore@gmail.com			
क्रमांक-जीसीएस/स्था/2026/2726			दिनांक-19 मार्च 2026
ई-बोली सूचना संख्या 1/2025-26			
इस माध्यमिक से Smart Class शुरू करने हेतु सभी निविदा सूचना क्रमांक 01/2025-26 आमंत्रित की गयी है। जिससे अनुमानित लागू खर्च 196000/- (अक्षर अक्षर लाख नौ हजार रुपये मात्र) है।			
1. निविदा बेनेने की तिथि व समय	18.03.2026 से 28.03.2026 सुबह 11.00 बजे तक		
2. निविदा जमा करनी की अंतिम तिथि व समय	27.03.2026 मध्याह्न १2.00 बजे तक		
3. निविदा बोली खोलने का समय	28.03.2026 को दोपहर 01.00 बजे तक		
छुकी निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट राजस्थान राज्य लोक उपायन पोर्टल http://rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।			
NIB NO.- ECD2526GA0657, UBN NO.- ECD2526GL0B00685			
(मूला राम) कार्यवाहक प्राचार्य एवं (सहायक आचार्य, भूगोल) राजकीय महाविद्यालय, सांचौर			
DIPRC/5971/2026			

 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
माध्यमिक, माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिक परीक्षा-2026 की उत्तर-पुस्तिकाओं की सर्वोक्षा एवं उत्तर-पुस्तिकाओं की स्केन कोटो प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों के सूचनाएं
माध्यमिक, माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका परीक्षा-2026 का परिणाम दिनांक 24.03.2026 को घोषित किया गया है। संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिका की स्केन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 31.03.2026 एवं विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 03.04.2026 तक ई-मित्र पर अथवा स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें व आवेदन पत्र प्रारूप/प्रक्रिया आदि बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एवं दिनांक 24.03.2026 को अपलोड की गई विज्ञप्ति में देखें।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड भीनमाल जिला जालौर						
क्रमांक- अ.अ./पी. /जनपरिचयन/निविदा/2025-26/3002-13						
बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 51-54/2025-26						
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जन स्वास्थ्य अभियंत्रिता विभाग, खण्ड भीनमाल ने निम्नलिखित व्यक्तों के लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिता विभाग में उपयुक्त क्षेपी में पंजीकृत जो उपयुक्त पत्राक्षर रखते हैं, संवेद्यता से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकते हैं। निविदा का विस्तृत विवरण एवं पत्राक्ष की शर्तें वेबसाइट www.dipronline.org , www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा ऑनलाइन उत्तेरपुस्तिका फॉरवर्ड http://eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जानी है।						
क्र. सं.	विवरण	अनु. लागत (लाखों में)	प्रतिशत राशि 2 धरखर्च	निविदा शुल्क	प्रोप्रेसिड शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
51/ 2025-26	खण्ड भीमाल के अन्तर्गत उपखण्ड भीमाल बाहर में समरथास्त बरिसवो/वाडी के लिए जल परिवहन का कार्य।	5.00	10000/-	500/-	500/-	वार्षिक
52/ 2025-26	खण्ड भीमाल के अन्तर्गत उपखण्ड रानीवाडा में समरथाप्रस्त गाँवो के लिए जल परिवहन का कार्य।	41.90	83800/-	500/-	500/-	वार्षिक
53/ 2025-26	खण्ड भीमाल के अन्तर्गत उपखण्ड जसवंतपुर में समरथाप्रस्त गाँवो के लिए जल परिवहन का कार्य।	33.40	66800/-	500/-	500/-	वार्षिक
54/ 2025-26	खण्ड भीमाल के अन्तर्गत उपखण्ड भीमाल ग्रामीण में समरथाप्रस्त गाँवो के लिए जल परिवहन का कार्य।	52.50	105000/-	1500/-	1500/-	वार्षिक
निविदादाता को आसटी एक 2000 के तहत डिजिटल सिगनेचर सॉर्टफिकेट प्राप्त कर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त निविदा प्रस्तुत करनी होगी। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।						
पानी बचाओ-जीवन बचाओ				दिनांक-19.03.2026		
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि				19.03.2026		
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय				27.03.2026 मध्याह्न १२.00 बजे तक		
ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय				27.03.2026 मध्याह्न १२.00 बजे तक		
प्री-क्वालिफिकेशन बीड खोलने की तिथि एवं समय				28.03.2026 मध्याह्न १२.00 बजे तक		
DIPRC/5992/2026				(प्रधान कुमार) अधिशाषी अभियन्ता जन.स्वा.अभि. विभाग खण्ड भीनमाल		

 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
माध्यमिक परीक्षा-2026 की उत्तर-पुस्तिकाओं की सर्वोक्षा एवं उत्तर-पुस्तिकाओं की स्केन प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु ह
माध्यमिक परीक्षा के अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय में पुनः जांच (Re-Examination) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के सूचनाएं
माध्यमिक परीक्षा-2026 के प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी, परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि से 07 दिवस में एवं उसके परचातू पश्चात् 03 दिवस में विलम्ब शुल्क से स्तर पुस्तिका की सर्वोक्षा करने एवं सर्वोक्षा उपरान्त स्केन प्रति प्राप्त करने हेतु बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर SCRTUTINY-2026 लिंक पर निमत लिंक तथा (एन्वामागत आई.डी. अक्सेस कर) ई- मित्र अथवा अन्यथा स्वयं के स्तर से बोर्ड वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग/बैंकिट/क्रेडिट कार्ड से तथा ई-मित्र से आवेदन करने पर शुल्क (देवा शुल्क सहित) ई-मित्र पर जमा कराया होगा। विस्तृत जानकारी बोर्ड वेबसाइट से ली जा सकती है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम (13) (5) के प्रावधान अनुसार सर्वोक्षा में उत्तर-पुस्तिकाओं में पुनःजांच (Re-Examination) करना समाविष्ट नहीं है। सर्वोक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अन्वे के योग में फिलहाल, अन्तर-बाहर (अंग्रेज) में फिलहाल, योग व कुट्टि, फिलहाल व अन्वे नहीं दिये गये हैं, उत्तर पुस्तिका/अन्वलिपिका में प्रदत्त अन्वे में फिलहाल अति कुट्टि का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। माध्यमिक परीक्षा के अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय में पुनःजांच (Re-Examination) करने का प्रावधान किया गया है।
अन्तिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध/पंजीकरण कर SMS द्वारा परीक्षार्थी के प्रश्न-पत्र में अंकित मोबाइल नं. पर पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों को सूचना अन्तिम दिनांक के परचातू दी जायेगी। सर्वोक्षा की निमत प्रक्रिया द्वारा निविदा निस्तारित प्रकरणों का परिणाम/अपेक्षित विषय की उत्तर-पुस्तिका वेबसाइट पर दिये गये पर अक्सेस कर आवेदित मोबाइल नं. पर SMS द्वारा 'Password' उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका ऑनलाइन टैबलट/स्मार्टफोन/स्मिंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षार्थी अपना स्वयं का सही मोबाइल नम्बर व ई-मेल अंकित करेंगे। मोबाइल नं. व ई-मेल लॉक अंकित करने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। एक मोबाइल नम्बर व ई-मेल को एक बार ही प्रयुक्त किया जा सकेगा। ई-मित्र क्रियोव्क धारक का मोबाइल नम्बर/ ई-मेल ट्रैक करना अनुरक्षित एवं निर्यात विकसद्ध माना जावेगा।
सभी विषयों में सर्वोक्षा परिणाम का संदेश प्राप्त होने की तिथि से निम्नीरत 05 दिवस की अवधि में उ.पु. कर अक्सेसकर कर यदि कोई आवेष्ट हो तो निक्कटतम ई-मित्र द्वारा अथवा सीधे आवेदन-पत्र धारक/प्रमाण सत्यान कर निम्नीरत शुल्क रु. 100/- प्रति विषय के साथ में ऑनलाइन अक्वित दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
माध्यमिक परीक्षा के परीक्षार्थी अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय में सर्वोक्षा उपरान्त अपनी पुनःजांच (Re-Examination) करना सभाव्य है। अक्वित शुल्क रुपये 100/- प्रति विषय तथा पुनःजांच (Re-Examination) शुल्क रुपये 100/- प्रति प्रश्न पत्रों। पुनःजांच (Re-Examination) हेतु आवेदन पत्र में प्रपत्र संख्या व पृष्ठ संख्या अवशिष्ट रूप से अक्वित करने। सर्वोक्षा परिणाम के SMS/E-mail भेजने की तिथि से 05 दिवस की निमित्त अवधि में ही अपेक्षित पुनःजांच (Re-Examination) हेतु ऑनलाइन ही आवेदन करने का सकेगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
नोट : 1. विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें आवेदन पत्र प्रारूप/प्रक्रिया आदि बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 2. सम्बन्ध परीक्षार्थी के परिणाम घोषणा तिथि से उत्तर निमित्त सम्बन्धार्थी ने आवेदन किया जा सकता है। 3. निम्नीरत तिथि के बाद व इसके पश्चात आवेदन-पत्र व अपेक्षित शुल्क नहीं होगा। 4. किसी भी दिवस को प्रश्नपत्र/अपेक्षक अपेक्ष सर्वोक्षा की कवामन STATUS की जानकारी बोर्ड वेबसाइट पर 'SCRTUTINY-2026' लिंक पर प्राप्त की जा सकती है। 5. एक परीक्षार्थी को आवेदन टुट्ट एक ही अवसर देय होगा। अतः एक बार ही आवेदन में वरिष्ठ सभी विषय (मैट्रिमाथ/प्रयोगिक) अक्वित करें। 6. सर्वोक्षा/आपेक्षित पुनः जांच (Re-Examination) में अक्वें में कमी अथवा वृद्धि के उपरान्त परिणाम/अंको में संशोधन होगा तत्पुस्तक परिणाम/संशोधित अंके प्रपत्नी होने एवं उरवी अनुपुष संशोधित अक्वलिपिका जारी की जायेगी। 7. सर्वोक्षा उपरान्त अपेक्षित विषय/विषयों में अंके परिवर्तन होने अथवा नहीं होने की किसी भी स्थिति में सर्वोक्षा शुल्क सौटायन नहीं जायेगा।

“राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026” से प्रदेश को मिलेगी वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक पहल

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में “राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026” जारी कर ऐतिहासिक पहल की गई है। इस नीति के जरिए ना केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी।

वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक बन रहा है। यह नीति राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने तथा आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

असेम्बली एण्ड टेस्ट (वैजु) के साथ असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एण्ड पैकेजिंग (जड्जु) और सेंसर के क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति सेमीकंडक्टर के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही उच्च तकनीक पर आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित भी करेगी। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होकर इससे जुड़ी पूरी वैल्यू-चेन

- निवेश, रोजगार, कौशल और तकनीकी नवाचार की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम
- केन्द्रीय बजट में भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

को कवर करती है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए गए हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। इसी के मद्देनजर जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकोणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए

जाएंगे। इससे उद्योगों को भूमि आवंटन व सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। साथ ही, विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास और फैबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैचरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट्स को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, स्टाम्प शुल्क व भू-रूपान्तरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सस्मिडी का 60 प्रतिशत अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।

औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स की लागत का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।देश में मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। केन्द्रीय बजट में भी “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0” के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, ‘प्रोडक्शन लिंकड इन्सॉटिव’ के लाभ भी दिए जा रहे हैं। ये कदम देश को तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों के साथ खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं और राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 के जरिए प्रदेश इस सैराथन में अपना अहम योगदान देने जा रहा है।

व्हाट्सएप के जरिए भेजा नोटिस सीआरपीसी के तहत वैध नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने को अवैध ठहराया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल व्हाट्सएप के जरिए भेजा नोटिस कानूनी तौर पर सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत वैध नहीं है। वहीं ऐसे नोटिस के आधार पर की गई गिरफ्तारी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुर्णेद्र

सिंह राठौड़ को अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा के बिंदु पर 6 अप्रैल को पेश होने को कहा है। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश आरएसएलडीसी में हुए घूसकांड से जुड़े मामले में रवि मीणा की अवमानना याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि नोटिस का तामील कानून में निर्धारित प्रक्रिया यानि व्यक्तिगत तामील, चस्मा और स्पीड पोस्ट आदि से ही होनी चाहिए। यदि आरोपी नोटिस का पालन करता है, तो उसे बिना ठोस कारण गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।

याचिका में अधिवक्ता अधिवक्ता

मोहित खंडेलवाल ने बताया कि मामले में एसीबी ने याचिकाकर्ता को एक फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले एसीबी के जांच अधिकारी ने 25 जनवरी, 2023 को उसे व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा और 31 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। इस पर उसने एसीबी के नोटिस का जवाब देते हुए अपनी पत्नी की बीमारी के कारण समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए ही उसे सीधे ही गिरफ्तार कर लिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 41 ए की अवहेलना है और मामले में कानूनी

प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। इसके जवाब में एसीबी ने कहा कि उन्होंने आरोपी को नोटिस दिया था, लेकिन उसने जवाब में टालमटोल का रवैया रखा। इसके अलावा याचिकाकर्ता एकआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और असफल रहे हैं। इसके बाद ही अनुसंधान एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए उसने यह अवमानना याचिका दायर की है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर एसीबी की गिरफ्तारी की कार्रवाई को गणत मानते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तलब किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चाचाजी का निधन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चाचाजी रामचरण लाल शर्मा का निधन हो गया। ये पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और मानसरोवर स्थित अमर हॉस्पिटल में उनका उपचार जारी था। मंगलवार को सीएमओ से रवाना होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानसरोवर स्थित अस्पताल पहुंचे, जहाँ उन्होंने स्व. चाचाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाँढस बंधाया और दुख की इस घड़ी में हिम्मत बनाए रखने की बात कही। परिजनों और नजदीकी लोगों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कुछ समय तक अस्पताल में रहे।

“टीबी मुक्त भारत अभियान” का शुभारंभ

जयपुर (कासं)। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राज्य में टीबी मुक्त भारत अभियान-100 दिवसीय का शुभारंभ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवर की उपस्थिति में किया गया।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि टीबी (क्षय रोग) केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति एवं परिवार को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनौती है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1 करोड़ 7.5 लाख से अधिक संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की है, जो देश में सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित उच्च जोखिम वाले ग्रामों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना एवं टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है।

खींवर ने कहा कि यह 100 दिवसीय अभियान जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन का रूप लेगा तथा प्रत्येक मरीज तक समय पर जांच



एवं उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा नोएडा में किए गए शुभारंभ कार्यक्रम को ऑनलाइन वीसी के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों और जन समुदाय के साथ सुना और टीबी रोगियों को निश्चय पोषण किट का वितरण भी किया।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान ने डेटा एवं तकनीक आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उच्च जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है। राज्य के 11 हजार 184 चिन्हित ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में शिविरों के

माध्यम से टीबी उन्मूलन की गति को और तेज किया जाएगा। मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य शिविरों के माध्यम से टीबी के साथ-साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं अन्य गैर-संचारी रोगों की भी जांच की जाएगी, जिससे आमजन को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। निदेशक जन स्वास्थ्य, डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने शिविरों में 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी, जिसमें टीबी स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बाँड़ी मास इंडेक्स, छाती का एक्स-रे शामिल होंगे।

सहकारिता मंत्री ने ‘ क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2025 ’ प्रदान किए

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर । सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से लाभान्वित करने के प्रयास कर रही है। दक मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को एनसीडीसी के ‘क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार-2025’ प्रदान किया। दक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को पहचानकर वर्ष 2021 में अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन कर अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद विगत 4 वर्षों में देश में सहकारी क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। सहकारी आन्दोलन आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाने के संकल्प की ओर देश को ले जाने में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा पर विगत अक्टूबर माह में सहकार



सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए।

सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें सहकारी समितियों के लगभग 9 लाख नये सदस्य बनाये गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 120 से अधिक पहलें क्रियावित्त की जा रही है। इन पहलों को अपानाकर सहकारी समितियां सशक्त बन रही हैं। उन्होंने सहकारी समितियों द्वारा क्षेत्रीय उत्पादों का विपणन एवं निर्यात करने की

आवश्यकता पर जोर दिया। सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों की ऑडिट एवं आमसभा समय पर करवाये जाने एवं आमसभा में सभी के सुझाव लिए जाने पर भी बल दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किशनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष चेतन चौधरी ने कहा कि केन्द्र में अमित शाह एवं राज्य

- सहकारी समितियों में नये लोगों को भी मिले कार्य करने का समुचित अवसर : गौतम दक

में गौतम कुमार दक के निर्देशन में सहकारी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में सहकारी समितियों में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है तथा कृषि जिसों की समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों का जीवन स्तर सुधर रहा है।

एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक सुनील कुमार छापोला ने बताया कि संस्था द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अच्छा कार्य करने वाली समितियों को प्रत्येक दो वर्ष में राज्य स्तर पर उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत टॉफी, प्रमाण पत्र एवं 35 हजार रुपये की राशि एवं श्रेष्ठता पुरस्कार के अंतर्गत टॉफी, प्रमाण पत्र व 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। प्रारम्भ में सहकारिता मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग व एनसीडीसी के अधिकारियों सहित सहकारी समितियों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

खनन विभाग का फोकस अगले 7 दिन तय राजस्व संग्रहण लक्ष्य हासिल करने पर : अपर्णा अरोरा

12 प्रतिशत विकास दर के साथ गत वर्ष से 1000 करोड़ रु. अधिक राजस्व संग्रहित किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने खान विभाग के फील्ड अधिकारियों को आगामी 7 दिनों में मार्च माह के निर्धारित 1550 करोड़ रुपए के लक्ष्यनुसार शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन गतिविधियों कार्रवाई के दौरान की जुर्माना राशि वसूलने, आरसीसी – ईआरसीसी ठेकों के ऑक्शन व देय रॉयल्टी की वसूली, एसएमई स्तर पर राजस्व संग्रहण की दैनिक समीक्षा, विप्लेपण व मार्गदर्शन, मुख्यालय स्तर से नियमित समीक्षा व राजस्व वसूली में कमी वाले कार्यालयों से समन्वय व वसूली में तेजी लाने, पुरानी बकाया की वसूली और करन्टे बकाया की शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों से वसूली के कारण प्रयास किये जाने हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव खान अपर्णा अरोरा मंगलवार को सचिवालय से राजस्व लक्ष्यों की वसूली के संबंध में हाईब्रीड मोड पर फील्ड अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रही थी। उन्होंने बताया कि 12 प्रतिशत विकास दर के साथ 23 मार्च तक 9620 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया जा



चुका है यह गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि खान विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों में से एक है ऐसे में राजस्व संग्रहण में किसी भी स्तर पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

अरोरा ने कहा कि आगामी सात दिनों में विभाग का प्रमुख फोकस राजस्व संग्रहण होने के साथ ही आरसीसी-ईआरसीसी ठेकों की नीलामी सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा। हाईब्रीड बैठक के दौरान उन्होंने

- राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों से कारणर वसूली करके 1550 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास
- 23 मार्च तक 9620 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित कर चुके : अरोरा

एसएमई स्तर के सभी अधिकारियों से संवाद कायम किया और राजस्व वसूली के कारणर प्रयासों के निर्देश दिए। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माधुर ने राजस्व वसूली लक्ष्यों और उनके अनुसार वसूली प्राप्ति से अवगत कराया। उन्होंने राजस्व संग्रहण के विभागीय रोडमैप की जानकारी देते हुए विश्वास दिलाया कि मार्च माह के निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाएगा।

हाईब्रीड बैठक में विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, वित्तीय सलाहकार सुरेश चन्द्र व विभाग के अधीक्षक खनि अभियंता, खनि अभियंता और सहायक खनि अभियंता स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

छात्रसंघ चुनाव को लेकर आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति अल्पना कटेजा से जवाब तलब किया

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर विवि की कुलपति अल्पना कटेजा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश नीरज खींचड की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तुषार पंवार ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 19 दिसंबर को छात्रसंघ चुनाव कराने के संबंध में दायर याचिका को निस्तारित किया था। इस दौरान अदालत ने विवि प्रशासन को निर्देश दिए थे

कि वह 19 जनवरी, 2026 को चुनाव के संबंध में बैठक करे और उसके पन्द्रह दिन में इस बैठक में हुए निर्णय को नोटिफाई करे।

अवमानना याचिका में कहा गया कि विवि प्रशासन ने बैठक के निर्णय को तय अवधि बीतने के बाद भी नोटिफाई नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर अदालती आदेश की अवमानना कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अदालती आदेश की अवमानना के लिए दंडित करते हुए आदेश की पालना कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विवि की वीसी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में एक 9वीं क्लस की नाबालिग छात्रा से गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के बयानों के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।

गौरतलब है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा पिछले सप्ताह लापता हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी सहायता के आधार पर नाबालिग छात्रा को दिल्ली से दस्तयाब कर लिया।

पुलिस पृष्ठताछ में सामने आया की उसकी सहेली ने एक युवक से उसकी जान पहचान कराई थी। गत पांच दिन पहले आरोपी युवक ने उसे मिलने का झांसा देकर बुलाया और अपने दोस्त के

साथ मिलकर उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया और दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर मारने की धमकी देकर डराया। धमकाने पर पीडित डर गई और दिल्ली भाग गई।

पुलिस ने नाबालिग पीडिता के बयान दर्ज कर गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को दबोच लिया। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त से दूसरे साथी के बारे में गहनता से पृष्ठताछ करने में जुटी है।

गाली-गलौच के बाद रिश्तेदारों ने किया अधेड़ पर प्राण घातक हमला

जयपुर। नारायण विहार थाना इलाके में मामूली कहासुनी के बाद रिश्तेदारों ने अंधेड़ युवक पर लाठी-डंडों से प्राण घातक हमला कर दिया और पीडित को बुरी तरह जखमी करने के बाद मौके से फरार हो गए।

आरोपियों के चुगल से मुक्त होने के बाद पीडित ने मामले की जानकारी अपने जवाई को दी। जवाई ने मौके पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। मेडिकल इतला पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने पच्ची बयान के आधार पर आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि कनक विहार, धाबास निवासी लल्लू लाल शर्मा रविवार 22 मार्च को किसी निजी स्कूल के शुभारंभ में शामिल होने आए थे। इसी दौरान रिश्तेदार मोहन लाल शर्मा श्रीराम कॉलोनी निवासी ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गाली-गलौच कर दी। अन्य लोगों की समझझंश पर मोहन लाल वहां से चला गया।

कार्यक्रम समापन के बाद जैसी ही पीडित वहां से निकला तो रिश्तेदार मोहन लाल शर्मा अपने पुत्र आर्यन ,वहनेई विष्णु व एक अन्य युवक के साथ गणपति नगर में पीडित को रोक

- तीन-चार जनों ने लाठी-डंडों से हमला कर अधेड़ को किया लहलुहान
- मौके पर भीड़ जमा होती देख स्कॉर्पियो गाड़ी से हुए फरार आरोपी

लिया और उसके स्कूटर की हवा निकाल दी। जिसके बाद सभी ने एक राय होकर लाठी-डंडों से पीडित से जानलेवा हमला कर दिया।

आरोप है की मारपीट के दौरान आरोपी रिश्तेदार मोहन लाल शर्मा ने पीडित के गले में पहनी हुई सोने की चेन छीन ली और उसके पुत्र आर्यन ने पीडित की जेब में रखे 18 हजार रुपए निकाल लिए।

चीख-पुकार की आवाज सुन कुछ लोग पीडित को बचाने पहुंचे तो आरोपी रिश्तेदार मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पीडित के जवाई ने उसे निजी अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने पीडित के बयानों के आधार पर आरोपी रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

एनडीपीएस मामले में फरार 10 हजार की इनामी महिला गिरफ्तार

जी.आर.पी. थाना पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया

जयपुर। जीआरपी थाना पुलिस ने काफी लंबे समय से अवैध मदक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रही इनामी महिला तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर महिला से फरारी काटने व सहयोग करने वालों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

पुलिस मुख्यालय ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया था। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 10 हजार की इनामी महिला तस्कर शिवाली बेगम (32) को बैंगलूरु निवासी को उसके निवास स्थान पर दबोच लिया। वह एनडीपीएस एक्ट और आर्यस एक्ट में काफी लंबे समय से वांछित चल रही थी। विशेष अभियान

के तहत ये कार्रवाई एडीजीपी रेलवे सुभित विश्वास, आईजी रेलवे अजय पाल लाम्बा और जीआरपी अजमेर के पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की गई। एडिशनल एसपी जीआरपी अजमेर और वृताधिकारी जीआरपी जयपुर के सुपरविजन में थाना प्रभारी अरुण चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था।

इनामी महिला तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम ने तकनीकी संसाधन का प्रयोग करते हुए उसे लगातार ट्रैस किया। जिसके बाद टीम में शामिल थाना प्रभारी अरुण चौधरी सहित जगदीश प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), प्रकाश चंद, रामचंद्र, माणक चंद और महिला कॉन्स्टेबल सरिता ने बैंगलूरु से महिला तस्कर को दबोच लिया।

**धार पर दो नामजद और
मलाफ धोखाधड़ी का मामला
ने है और आरोपियों की**

फिन कॉर्प लिमिटेड की शाखा में सोना जमा करवाने की बजाय बहाने बनाता रहा। 17 मार्च को सरूप सिंह अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। शाखा प्रबंधक सुमन ने अपने स्तर पर पड़ताल की तो पूरी सजिष्य का खुलासा हुआ। आरोप है कि सरूप सिंह और सोनू सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से कंपनी से राशि ट्रॉंसफर करवाई और सोना लेकर गायब हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

राजस्थान की धरा शौर्य , आस्था व भक्ति की त्रिवेणी - भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बालोतरा के कनना श्रीमठ में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया

बालोतरा, 24 मार्च (नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजनीति हो या अन्य कार्य, धर्म आवश्यक है, धर्म के अभाव में कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता। सनातन परम्परा हमें धर्म पर चलते हुए सामाजिक एकता के साथ आगे बढ़ने

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले एक वर्ष से चल रहे श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में देश भर से आए प्रमुख संत-महंतों का दुष्टा ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। महंत परशुराम गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री को श्रीयंत्र भेंट कर अभिनंदन किया।**

की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरा शौर्य , आस्था और भक्ति की त्रिवेणी है, जहां साधु-संतों के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है।

श्रीमं गंगलवार को बालोतरा के कनना श्रीमठ में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं मां सरस्वती

अमेरिका व ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वितीय और तेल बाजार को प्रभावित करने और उस संकट से निकलने के लिए एक्सा जा रहा है, जिसमें अमेरिका और इज़राइल फंस हुए हैं।”

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी पर्दे के पीछे तेहरान और ट्रंप टीम के दूतों, विटकोंफ और जारेड कुशनर, के बीच बातचीत करा रहे थे। साथ ही, प्रधानमंत्री शरीफ ने युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार पेजेशियन से बात की है।

सोमवार को हुई बातचीत के बारे में जारी एक बयान में 'पाकिस्तान ने कहा, “प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति को पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि पाकिस्तान शांति स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा।”

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कथित रूप से पिछले सप्ताह रियाद में हुई बैठक में अरब देशों के प्रतिनिधियों से कहा कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है, हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। एक राजनयिक ने फार्मेशनैशियल टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान ही इस मध्यस्थता प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

पाकिस्तान, जहाँ कोई भी अमेरिकी सैन्य अड्डे नहीं है, इस क्षेत्र के उन गिने-चुने अमेरिकी सहयोगियों में से एक है, जो तेहरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रहे हैं। इससे पाकिस्तान को ईरान और यू.एस. के बीच एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली है। पाकिस्तान में ईरान के बाद

‘ धनखड़ के ईस्तीफे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
“अनलाइकली पैराडाइज़” के अपडेटेड अंग्रेजी संस्करण में राउत ने लिखा है कि धनखड़ को जांच एजेंसियों की धमकी देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि एनडीए सरकार को उनके “स्वतंत्र फैसले” पसंद नहीं थे। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरक ओ’ब्रायन मौजूद थे।

सोमवार को नई दिल्ली में विमोचित इस पुस्तक में राउत ने दावा किया कि ईडी ने धनखड़ के खिलाफ उनकी संपत्ति के सौदों और विदेशी खातों में भेजी गई रकम को लेकर एक फाइल तैयार की थी। राउत ने लिखा: “अफवाहें फैली थीं कि धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया और उसकी कुछ राशि विदेश भेज दी। ईडी, जो उनकी गतिविधियों पर बारीक नज़र रख रही थी, ने कथित तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक फाइल तैयार की। इस काम में अन्य जाँच एजेंसियां भी शामिल थीं। जब मोदी सरकार के खिलाफ धनखड़ के स्वतंत्र राजनीतिक कदमों की चर्चा होने लगी, तो ईडी ने कथित तौर पर यह फाइल उनके सामने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बालोतरा के कनना श्रीमठ में आयोजित श्रीललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं मां सरस्वती मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया।

मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के साथ ही, आने वाली पीढ़ी को विरासत से जोड़ते हैं।

मुख्यमंत्री ने बालोतरा के धार्मिक महत्व को बताते हुए कहा कि यहां के तीर्थ स्थल हमारी गौरवशाली संस्कृति के सजग प्रहरी हैं। वहीं, कनाना मठ की पवित्र भूमि अलौकिक ऊर्जा का संचार करती है।

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मंदिरों के विकास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान, कनाना मठ के महंत परशुराम गिरि महाराज ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन अखण्ड भारत और सनातन संस्कृति की पहचान हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पिछले

‘वाॅशिंगटन से संदेश आया, ट्रंप समझौता चाहते हैं’

ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी

- ज्ञातव्य है कि इससे पहले तक ट्रंप के ईरान से वार्ता चलने के दावे का ईरान ने ही खंडन किया था।**

अनुसार, ईरानी अधिकारी ने कहा, “हमें मध्यस्थों के माफ़त अमेरिका से कुछ सार्थक संदेश मिले हैं। हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं।” इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है।”

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के

ईरान के शीर्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
दुलमूल है। कुछ महीने पर उन्होंने हमलों को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी बताया, वहीं कई अन्य जगहों पर इसे क्षेत्रीय युद्ध को टालने के लिए पूर्व निर्धारित कदम बताया। इस बदलते रुख ने आलोचना को जन्म दिया है कि प्रशासन के पास स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण की कमी है।

आंतरिक मतभेद के संकेत देते हुए, ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सैन्य कार्रवाइ के खराब समर्थक नहीं थे, हालांकि वेंस ने सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं जताया है। यह बयान प्रशासन के भीतर संभावित मतभेदों की ओर इशारा करता है, जबकि वाॅशिंगटन बाहर से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है।

हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया कितनी व्यापक और घातक हो सकती है, इसका सही आकलन नहीं हुआ। ट्रंप ने स्वीकार किया कि अमेरिका ने यह उम्मीद नहीं की थी कि तेहरान खाड़ी देशों पर जवाबी हमले कर देगा। इन हमलों ने संघर्ष के भौगोलिक दायरे को बड़ा दिया है और व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दिया है। ईरान के बाद के कदम, जिसमें होर्मुज़ स्ट्रेट में आवाजाही को प्रभावित रूप से बाधित करना शामिल है, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापार मार्गों को झकझोर दिया है।

ट्रंप ने अपने रुख में उल्लेखनीय बदलाव करते हुए सोमवार को ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे हमला करने में अस्थायी विराम की घोषणा की। दृढ़ सोशल पर पोस्ट किए गए बयान में उन्होंने कहा कि वाॅशिंगटन ने ऐसे सभी सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए टालने का फैसला किया है, जो तेहरान के साथ चल रही वार्ताओं में प्रगति पर निर्भर करेगा।

ट्रंप ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और सकारात्मक वार्ता हुई, जो मध्य पूर्व में हमारी शत्रुता के पूर्ण समाधान की दिशा में एक कदम है।

दिल्ली वालों को दो फ्री सिलैण्डर मिलेंगे

—जाल खंबाता —
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 मार्च। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। इस बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और पर्यावरण पर जोर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का 2026-27 का बजट पेश करते हुए घोषणा की।**

हालांकि रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की “फ्रीबी संस्कृति” की खूब आलोचना की, लेकिन साथ ही, बजट में 2 मुफ्त एलजीपी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। 1,03,700 करोड़ रुपये का यह बजट राजधानी के सबसे बड़े बजटों में से एक है। सरकार ने इसे ग्रीन बजट का नाम दिया है, हालांकि इसमें सड़कों, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं पर भी बड़ा खर्च रखा गया है। पिछले साल उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

हरीश राणा ने ली अंतिम सांस

नई दिल्ली, 24 मार्च। देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथनेशिया) की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरिश राणा का मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। एम्स ने जारी एक बयान में कहा कि हरिश राणा ने मंगलवार को

शाम 4.10 मिनट पर अंतिम सांसें लीं। वे समर्पित चिकित्सकों की टीम की देखरेख में थे और उन्हें ऑन्को-एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष, डॉ. (प्रो.) सोमा मिश्रा पर एक ऐतिहासिक निष्ण्य माना गया था।हरिश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को विशेष अनुमति देते हुए

‘हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर एससी का दर्जा नहीं मिलेगा’

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने से अनुसूचित जाति की दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है।**

ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा, किसी और धर्म को अपनाने पर, जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि खंड 3 के तहत, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना

जाता है, वह संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता और न ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा, किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता।”

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।

सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहें

वाॅशिंगटन, 24 मार्च। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रम्प से कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रखी जाए। उनके मुताबिक, यह मिडिल ईस्ट को बदलने का एक बड़ा मौका है। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है।

अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। क्राउन प्रिंस ने पिछले हफ्ते ट्रम्प से बातचीत की थी और कहा था कि अमेरिका को ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म कर देना चाहिए।

उनका मानना ​​है कि ईरान खाड़ी देशों के लिए लंबे समय का खतरा है और इस खतरे को सिर्फ शासन बदलकर ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन सऊदी सरकार ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। उसने

- वहां के क्राउन प्रिंस ने पिछले सप्ताह ट्रंप से कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म कर देना चाहिए।**

कहा कि सऊदी अरब हमेशा इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

इस बीच, सऊदी और अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि अगर युद्ध लंबा चला, तो ईरान सऊदी तेल ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। और अमेरिका एक लंबी लड़ाई में फंस सकता है।

पश्चिम एशिया संकट पर आज सर्वदलीय बैठक

केन्द्र सरकार की पहल पर संसद परिसर में बैठक आयोजित होगी

- विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, पश्चिम एशिया संकट से निपटने के मुद्दे पर सरकार के मुखर आलोचक हैं पर चर्चा है कि राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं होंगे।**

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार केरल जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पश्चिम एशिया संघर्ष से निपटने के सरकार के तरीके पर निशाना साधा।

राज्यसभा में सांसद जॉन ब्रिट्रास ने 2003 के उस संसदीय प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें इराक युद्ध की

निंदा की गई थी, और सरकार से ईरान के मामले में भी इसी तरह का रुख अपनाने की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया संघर्ष को न्यायप्रधान विचारों पर बात की। उन्होंने सभी राज्यों से केन्द्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में यह जरूरी है कि संसद का उच्च सदन शांति और संवाद का एकजुट संदेश दे।

तृणमूल ने कई राज्यों में भाजपा सरकारों द्वारा कई प्रकार के मीट, जैसे बीफ आदि पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया है और दावा किया है कि सत्ता में आने पर यह पार्टी बंगालियों के खान-पान पर भी सख्ती कर सकती है। बनर्जी ने बार-बार भाजपा पर “खाद्य नियंत्रण की राजनीति” करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर वे सत्ता में आए तो राज्य में मछली और मांस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ज्ञातव्य है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा था कि बंगाल में मांस की खुलेआम विक्री पर रोक लगा दी जाएगी। ममता बनर्जी ने सिन्हा के बयान को लेकर कहा है कि “वे बंगाल में मछली और मांस पर प्रतिबंध लगा देंगे, (जबकि) बंगाल मछली और चावल पर ही जीवित है।”

‘ भाजपा आई तो ...

कैलेंडर का सबसे बड़ा उत्सव, दुर्गा पूजा, भी मांसाहारी व्यंजनों के बिना अधूरा माना जाता है।

समय-समय पर सोशल मीडिया पर बंगालियों के खान-पान और हिंदू त्योहारों के दौरान मांसाहार को लेकर बहस छिड़ती रहती है। लेकिन, इस समुदाय के लिए यह उसकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप है। जब से भाजपा ने बंगाल में अपनी पकड़ सजबूत की है और मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी है, तृणमूल कांग्रेस को उसके खिलाफ मुख्य हथियार उसके “बाहरी” होने का नैरेटिव रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने भाजपा को बंगाल में एक ऐसी “बाहरी” ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जो राज्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नहीं समझती।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हुनगांव हथवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्य मैन चेंड आर्यड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रतृ भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी। 1/63, इन्दर्टीपल एरिया, फैस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

